www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 7.523

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
June 2023 Page No. : 152-159

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

ग्रामीण क्षेत्रों में नकद रहित लेन–देन से संबंधित चुनौतियों का अध्ययन

सुनील कुमार

असिस्टेंट प्रोफेसर (वाणिज्य विभाग), उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल।

सार :–

भारत में, नोटबंदी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में नकद रहित लेन–देन व्यापक रूप से उभरती हुई अवधारणा है। नकद रहित लेन–देन सुविधा और लेन–देन में आसानी है और नकद निकासी से जुड़े लेन–देन की तुलना में अधिक सुरक्षित है। नकद रहित लेन–देन शहरी और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के खरीदारी पैटर्न और खर्च करने के पैटर्न में बदलाव लाता है।

भारत धीरे–धीरे नकद–केन्द्रित से नकद रहित इकॉनमी की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल लेन–देन का पता लगाया जा सकता है, इसलिए आसानी से कर योग्य है, जिससे काले धन के संचलन के लिए कोई जगह नहीं बचती है। पूरा देश पैसे के लेन–देन में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, जिसमें ई–पेमेंट सेवाएं अभूतपूर्व गति प्राप्त कर रही हैं। बड़ी संख्या में व्यवसाय, यहां तक कि स्ट्रीट वेंडर भी अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार कर रहे हैं, जिससे लोगों को पहले से कहीं अधिक तेज गति से नकद रहित तरीके से लेनदेन करना सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नकद रहित सभी पहलुओं में बेहतर है। यह आर्थिक विकास में भी सहायक है। यह एक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और भुगतान किया जाता है। नकद रहित लेन–देन धन के प्रवाह को ट्रैक करना बहुत आसान हो जाता है, प्रत्येक लेनदेन को खरीदार, विक्रेता और साथ ही विनियमित निकायों के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे सिस्टम और अधिक पारदर्शी और अनुपालन हो जाता है।

भूमिका :–

नकद रहित लेनदेन का चलन दिन–ब–दिन नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग नकद रहित लेन–देन की ओर बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के अनुसार नकद रहित नीति से रोजगार में वृद्धि होगी, नकदी ले जाने के जोखिम को कम करके नकदी संबंधी डकैती को कम किया जा सकेगा। नकद रहित नीति से नकदी संबंधी भ्रष्टाचार भी कम होगा और अधिक विदेशी निवेशक देश की ओर आकर्षित होंगे। उम्मीद है कि इसका असर भुगतान प्रणाली के आधुनिकीकरण, बैंकिंग सेवा की लागत में कमी पर महसूस होगा।

आरबीआई प्रीपेड भुगतान साधन के रूप में कार्ड या मोबाइल फोन का उपयोग करके नकद रहित फंड

हस्तांतरण या लेनदेन के हर तरीके को वर्गीकृत करता है। सबसे लोकप्रिय, सुरक्षित और सर्वश्रेष्ठ डिजिटल भुगतान माध्यम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, मोबाइल बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट, ई–वॉलेट, ऑनलाइन ट्रांसफर आदि हैं। ये विधियाँ अधिक पारदर्शी हैं क्योंकि प्रत्येक लेन–देन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है क्योंकि यह अपने पैरों के निशान छोड़ देता है। कई शहरी लोगों ने नकद रहित भुगतान के नए विकल्प अपनाए। जहां ग्रामीण लोगों के लिए नकद रहित भुगतान विकल्प को अपनाना चुनौती है। क्षेत्र सर्वेक्षण के आंकड़ों पर हमने पाया कि अधिकांश ग्रामीण लोग डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं और बहुत कम लोग भुगतान के अन्य विकल्पों का उपयोग कर रहे हैं।

भारत के सभी राज्यों में, विमुद्रीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को नकद रहित लेन–देन में सुचारू रूप से परिवर्तित करने के प्रयास एक निरंतर और व्यापक रूप से उभरती हुई स्थिति रही है। और नकद रहित लेनदेन की मदद से आम लोगों की सुविधा और लेनदेन आसान हो गया है। और लेन–देन की तुलना में नकद निकासी से जुड़े संचालन अधिक सुरक्षित होते जा रहे हैं।

ई–कॉमर्स लेनदेन और डिजिटल भुगतान गेटवे के माध्यम से अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था की जीडीपी में वृद्धि होगी। इससे देश की साख बढ़ेगी और निवेश में वृद्धि होगी। नकद रहित का यह कदम वास्तव में बड़ी सफलता की लहरें पैदा करने वाला है।

भारत में कालाबाजारी से बचने के लिए देश धीरे–धीरे नकद–केंद्रित से नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। काले धन से बचने के लिए सरकार द्वारा निम्न प्रकार से भारत के अन्य राज्यों और भारत के कुछ हिस्सों में आसानी से डिजिटल भुगतान के माध्यम से भुगतान करने और लेने में एक मिनट भी नहीं लगता है।

योजना के क्रियान्वयन से सरकार ने इस कार्य को सुचारु रूप से आगे बढ़ाया, ताकि सरकार देश में कालाबाजारी को अधिकतम स्तर पर कम करने तथा डिजिटल भुगतान के माध्यम से नई तकनीक के साथ सुचारू रूप से कार्य कर सके। इसके जरिए समय पर भुगतान किया जा सकता है। इसके साथ ही ई–पेमेंट सेवाओं की अभूतपूर्व गति के कारण पूरा देश मुद्रा लेनदेन में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है।

इतना ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में सार्वजनिक और निजी स्केटर्स, यहां तक कि स्ट्रीट वेंडर भी अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार कर रहे हैं, जिससे लोग पहले से कहीं ज्यादा तेजी से नकद रहित लेनदेन कर सकते हैं।

नकद रहित हर लिहाज से बेहतर है क्योंकि कई बार नकद लेनदेन में डिजिटल पेमेंट से समय की बचत होती है। इसके अतिरिक्त इसे विधियों के साथ–साथ आर्थिक विकास में सहायक प्रक्रिया का रूप भी माना जा रहा है। यह उस आर्थिक व्यवस्था में भी एक मील का पत्थर साबित हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और उचित भुगतान किया जाता है। और प्रत्येक लेन–देन के साथ नकद रहित लेन–देन को खरीदार, विक्रेता और साथ ही विनियमित निकायों के साथ दर्ज किया जाना चाहिए। पैसे के प्रवाह को ट्रैक करना बहुत आसान है और आम जनता द्वारा इन प्रावधानों को एक डेस्क पर अपनाकर उचित रूप से किया जाता है ताकि लोग अपने स्वयं के पैसे का पंजीकरण कर सकें। समय का महत्व, इसकी कीमत आसानी से समझी जा सकती है। इसके साथ, सिस्टम अधिक पारदर्शी और आज्ञाकारी हो जाता है। ताकि नकद रहित भुगतान के कुछ विकल्प डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, मोबाइल बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट, ई–वॉलेट

और अन्य आदि हैं। कम समय में आम लोगों के माध्यम से डिजिटल भुगतान। सीमित समय में इस डिजिटल भुगतान और अन्य तरीकों को अपनाना ग्रामीण व शहरी लोगों के लिए और आसान हो गया है। कम से कम समय में, अधिक से अधिक रूप में, इस पूरे भुगतान को देश और विदेश में भी उजागर किया जा सकता है।

व्यवसाय और व्यक्ति अन्य लागतों से भी बच सकते हैं। चोरी अक्सर किसी की जेब में बड़ा छेद कर देती है। चोरी का जोखिम तब तक बना रहेगा जब तक कि लोग नकदी नहीं ले जाते और नकदी रहित होकर इसे कम किया जा सकता है। यह सरकार पर भी प्रभाव छोड़ता है क्योंकि वे उस लागत को कम कर सकते हैं जो सरकार दोषियों को पकड़ने पर खर्च करती है। अमेरिका जैसे देशों में, सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण भुगतानों को इलेक्ट्रॉनिक स्थानान्तरण में स्थानांतरित करने के बाद, चोरी और हमले में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है। हालांकि, सरकार को ऑनलाइन घोटालों और पहचान की चोरी की घटनाओं को रोकने के उपाय करने होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में नकद रहित लेन–देन से संबंधित चुनौतियों का अध्ययन :–

आज डिजिटल मीडिया के माध्यम से डिजिटल लेन–देन के प्रति लोगों की मानसिकता में बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि वे कम समय में अपना काम पूरा कर सकते हैं। देश की जनता को पता चल गया है कि डिजिटल लेन–देन सुरक्षित, आसान, सुविधाजनक और पारदर्शी भी है और भारत में काले धन और जाली मुद्रा की भारत में कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। नकद या नकद रहित इंडिया एक अभियान जागरूकता कार्यक्रम है जो हाल ही में सरकार द्वारा शुरू किया गया है कि भारत सरकार नकद आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आगे बढ़ रही है, डिजिटल माध्य से नकद, और इस प्रकार, देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव। उपरोक्त विश्लेषण से, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षित और कम शिक्षित लोग नकद रहित लेन–देन के बारे में जागरूक हैं। जब हम नकद रहित लेनदेन के उपयोग पर विचार करते हैं, तो अधिकांश उच्च शिक्षित लोग अक्सर नकद रहित लेनदेन का उपयोग कर रहे होते हैं। तकनीकी प्रगति, जानकारी की कमी, रुचि की कमी, उनकी उम्र, सुविधा की कमी, खराब धारणा आदि जैसे कई कारणों से निरक्षर लोग इस अवधारणा को अपने दैनिक जीवन में नहीं अपना सकते।

सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जाली मुद्रा के मामलों, भीड़ और बैंक के बोझ को कम करती है। डिजिटल भुगतान तंत्र भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने की दृष्टि से सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। आरबीआई भुगतान साधन के रूप में कार्ड या मोबाइल फोन का उपयोग करके नकद रहित फंड ट्रांसफर या लेनदेन के हर तरीके को वर्गीकृत करता है।

नकद रहित लेन–देन एक ऐसी आर्थिक स्थिति का वर्णन करता है जिसमें भौतिक बैंकनोट या सिक्कों के रूप में धन के साथ वित्तीय लेनदेन नहीं किया जाता है, बल्कि लेन–देन करने वाले पक्षों के बीच डिजिटल जानकारी के हस्तांतरण के माध्यम से किया जाता है।

नकद रहित ट्रांजेक्शन शब्द का अर्थ है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से लेन–देन के माध्यम से नकद लेन–देन और भुगतान के निपटान को कम करना। 8 नवंबर 2016 को सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को वापस ले लिया– दो सबसे बड़ी मुद्राएं प्रचलन से बाहर हो गईं। मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार, सुविधा, नकली धन और काले धन के खिलाफ लड़ना था।

आरबीआई प्रीपेड भुगतान साधन के रूप में कार्ड या मोबाइल फोन का उपयोग करके नकद रहित फंड ट्रांसफर या लेनदेन के हर तरीके को वर्गीकृत करता है। सबसे लोकप्रिय, सुरक्षित और सबसे अच्छा डिजिटल भुगतान माध्यम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, मोबाइल बैंकिंग, डिमांड ड्राफ्ट, ई–वॉलेट, ऑनलाइन ट्रांसफर आदि हैं। ये तरीके अधिक पारदर्शी हैं क्योंकि हर लेनदेन को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इसके पैरों के निशान। कई शहरी लोगों ने नकद रहित भुगतान के नए विकल्प अपनाए। जबकि ग्रामीण लोगों के लिए नकद रहित भुगतान के विकल्प को अपनाना एक चुनौती है। क्षेत्र सर्वेक्षण डेटा पर, हमने पाया कि अधिकांश ग्रामीण लोग डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहे हैं और बहुत कम लोग भुगतान के अन्य विकल्पों का उपयोग कर रहे हैं।

पूरा देश विमुद्रीकरण के प्रभावों को देख रहा है और हमारे प्रधान मंत्री द्वारा नकद रहित अर्थव्यवस्था पर संकेत देने से, बहुत से लोग भ्रम में रह गए हैं। नकद रहित अर्थव्यवस्था कैसे फायदेमंद होगी यह कई लोगों का सवाल है। नकद रहित ट्रांसफर जल्द ही सबसे पसंदीदा विकल्प बनता जा रहा है और नकद रहित होने के कई फायदे हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड आदि का उपयोग करके पूंजी का डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक लेन–देन नकद रहित ट्रांसफर कहलाता है।

लोग आसानी से अपने बिलों का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और लेन–देन निर्धारित कर सकते हैं और अपने लैपटॉप या स्मार्टफोन का उपयोग करके सभी वित्त का प्रबंधन कर सकते हैं। नकद रहित होने से न केवल किसी का जीवन आसान हो जाता है बल्कि किए गए लेन–देन को प्रमाणित और औपचारिक बनाने में भी मदद मिलती है। इससे भ्रष्टाचार और काले धन के प्रवाह पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास में वृद्धि होती है।

करेंसी नोटों की छपाई और परिवहन में होने वाला खर्च कम हो जाता है। भारत जैसे देश में, नकद रहित लेन–देन व्यापक नहीं है और यह तकनीकी अंतर और उचित शिक्षा की कमी के कारण है। हालांकि ये चिंता के विषय हैं, सरकार या वित्तीय संस्थानों को एक मजबूत नकद रहित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इनका समाधान करने की आवश्यकता है।

मोबाइल बैंकिंग एक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा है जो अपने ग्राहकों को स्मार्टफोन या टैबलेट जैसे मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके दूरस्थ रूप से वित्तीय लेनदेन करने की अनुमति देती है। मोबाइल बैंकिंग आमतौर पर 24 घंटे के आधार पर उपलब्ध है। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लेन–देन में खाता शेष राशि प्राप्त करना और नवीनतम लेनदेन की सूची, इलेक्ट्रॉनिक बिल भुगतान और ग्राहक या किसी अन्य के खातों के बीच धन हस्तांतरण शामिल हो सकते हैं। यह आपको देश भर में किसी भी स्थान से अपनी बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति देता है।

ऑनलाइन बैंकिंग, जिसे इंटरनेट बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम बनाती है। ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली आम तौर पर एक बैंक द्वारा संचालित कोर बैंकिंग प्रणाली से जुड़ती है या उसका हिस्सा बनती है और यह शाखा बैंकिंग के विपरीत है जो ग्राहकों द्वारा बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचने का पारंपरिक तरीका था।

क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नकद रहित भुगतान का एक और तरीका है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग कई उपयोगों के कारण लगातार बढ़ रहा है। डेबिट कार्ड के लाभ नकदी ले जाने की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं, वीजा और मास्टरकार्ड मर्चेंट स्वीकृति के कारण विश्वव्यापी कार्यक्षमता, क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करने या कर्ज में डूबने की चिंता नहीं है, 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति के लिए आवेदन करने और स्वीकार करने का अवसर क्रेडिट गुणवत्ता की परवाह किए बिना, और मुफ्त में कार्ड पर सीधे तनख्वाह और सरकारी लाभ जमा करने का विकल्प।

चेक नकद रहित भुगतान के लोकप्रिय तरीकों में से एक है। इस पद्धति में व्यक्ति किसी अन्य को विशिष्ट राशि के लिए चेक जारी करता है। व्यक्ति चेक को संबंधित बैंक में जमा करता है। दो दिनों के भीतर बैंक को राशि मिल जाती है। चेक की अधिकतम वैधता जारी होने की तारीख से तीन महीने की होती है। चेक के माध्यम से किया गया पूरा लेन–देन रिकॉर्ड हो जाता है और भुगतान का एक प्रमाण होता है। हालाँकि पर्याप्त बैलेंस न होने, हस्ताक्षर के बेमेल होने के कारण चेक के अनादर होने की संभावना होती है, चेक बुक में इन सभी मुद्दों से बचने के लिए लोग नकद रहित ट्रांजेक्शन के माध्यम से जा सकते हैं।

मोबाइल वॉलेट एक वर्चुअल वॉलेट है जो भुगतान कार्ड की जानकारी को मोबाइल डिवाइस पर संग्रहीत करता है। मोबाइल वॉलेट उपयोगकर्ता के लिए इन–स्टोर भुगतान करने का एक सुविधाजनक तरीका है और इसका उपयोग मोबाइल वॉलेट सेवा प्रदाता के साथ सूचीबद्ध व्यापारियों पर किया जा सकता है। एक मोबाइल वॉलेट आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी को आपके मोबाइल डिवाइस पर डिजिटल रूप में ले जाने का एक तरीका है।

डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से नकद रहित लेनदेन का लाभ अब स्थिर गति से फलने–फूलने लगा है और अधिक से अधिक लोग भुगतान प्राप्त करने और करने के डिजिटल तरीकों पर स्विच कर रहे हैं। भारत धीरे–धीरे नकद–केन्द्रित से नकद रहित इकॉनमी की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल लेन–देन का पता लगाया जा सकता है, इसलिए आसानी से कर योग्य है, जिससे काले धन के संचलन के लिए कोई जगह नहीं बचती है। पूरा देश पैसे के लेन–देन में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है, जिसमें ई–पेमेंट सेवाएं अभूतपूर्व गति प्राप्त कर रही हैं। बड़ी संख्या में व्यवसाय, यहां तक कि स्ट्रीट वेंडर भी अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार कर रहे हैं, जिससे लोगों को पहले से कहीं अधिक तेज गति से नकद रहित तरीके से लेनदेन करना सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों को अपनाने में वृद्धि के साथ, विशेष रूप से ई–कॉमर्स और एम–कॉमर्स चलाने वाले, तेजी से भुगतान सेवाओं की मांग बढ़ रही है, जो बदले में, वित्तीय लेनदेन करने में आसानी की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा, नकदी से दूर जाने से कर अपवंचकों के लिए अपनी आय को छिपाना अधिक कठिन हो जाएगा, जो कि आर्थिक रूप से विवश देश में एक बड़ा लाभ है।

नकद रहित लेनदेन की चुनौतियां :–

भारत में बड़ी संख्या में लोग अभी भी निरक्षर हैं और डिजिटल भुगतान विकल्पों का उपयोग करते समय धोखाधड़ी या अन्य कदाचार का शिकार हो सकते हैं। यहां सॉफ्टवेयर को संभालने के लिए प्रशिक्षण की कमी के कारण लोगों को डिजिटल पेमेंट करने का तरीका और डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना नहीं आता। कई स्ट्रीट वेंडर्स, दुकानदार स्वाइप मशीनों का उपयोग करना नहीं जानते हैं। साथ ही ये उन्हें उपलब्ध नहीं

हैं। ग्रामीण इलाकों में लोग अभी भी नहीं जानते हैं कि वास्तव में स्मार्टफोन का क्या मतलब है। उनके लिए मोबाइल आज भी संचार का एक माध्यम मात्र है।

इंटरनेट सुविधाओं का अभाव और इसके बिना कोई देश डिजिटल बनने की सोच भी नहीं सकता। अभी भी कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं जहाँ आपको 2जी नेटवर्क तक पहुँचने में कठिनाई हो सकती है, 3जी, 4जी को तो छोड़ ही दें। एक और मुद्दा यह है कि कभी–कभी यह नोट करना मुश्किल हो जाता है कि आपका लेन–देन सफल हुआ या नहीं। यह बीच में नेट कनेक्टिविटी के खराब होने, या धीमे कनेक्शन के कारण, या बैंक का सर्वर डाउन होने के कारण हो सकता है।

सबसे बड़ा डर पहचान की चोरी का खतरा है। चूँकि हम सांस्कृतिक रूप से डिजिटल लेन–देन के अभ्यस्त नहीं हैं, यहाँ तक कि पढ़े–लिखे लोग भी फिशिंग के जाल में फंसने का जोखिम उठाते हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के साथ, हैकिंग का खतरा तभी बढ़ेगा जब अधिक लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएंगे। इसके अलावा, सरकार द्वारा 2,000 तक के ऑनलाइन लेन–देन के लिए दो–कारक प्रमाणीकरण प्रक्रिया को हटाने के नवीनतम कदम से मदद नहीं मिलेगी। लेन–देन के आकार के बावजूद, सुरक्षा की इस अतिरिक्त परत के अभाव में हजारों लोगों को पहचान की चोरी के जोखिम का सामना करना पड़ेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों की शाखाएं नहीं हैं। कोई एटीएम मशीन या ई लॉबी सुविधा नहीं। कई गांवों में अब तक बिजली और दूरसंचार की सुविधा नहीं है। डिजिटल अर्थव्यवस्था की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता इंटरनेट और स्मार्टफोन की पैठ है। सभी भारतीयों के पास मोबाइल नहीं है, नेट कनेक्शन तो दूर की बात है। भारतीय दूरसंचार नियामक ट्राई, भारत के नवीनतम आंकड़ों में बिहार, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ 70 प्रतिशत से कम टेलीघनत्व के साथ टेलीघनत्व 83 प्रतिशत था। हालांकि एक बिलियन मोबाइल सब्सक्रिप्शन (उपयोगकर्ता नहीं), केवल 30 प्रतिशत ग्राहक ही स्मार्ट फोन का उपयोग करते हैं। 370 मिलियन मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, उनमें से 70 प्रतिशत से अधिक शहरों में हैं जबकि 70 प्रतिशत भारतीय आबादी गांवों में रहती है।

छोटे व्यापारियों के साथ–साथ उपयोगकर्ताओं में भी प्लास्टिक मनी को लेकर बहुत अधिक संदेह है और उन्हें इसके उपयोग के संभावित लाभों के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। प्लास्टिक मनी के उपयोग को लेकर अधिकांश भारतीयों की धारणा में रातोंरात बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार को जागरूकता और प्रोत्साहन योजनाओं के साथ आने की जरूरत है।

कार्ड जारी करने वाले प्राधिकरण या बैंक द्वारा एक व्यापारी द्वारा की जाने वाली प्रत्येक खरीदारी से ये प्रतिशत कटौती की जाती है। ये मात्रा पर निर्भर होते हैं और अधिक किफायती होते हैं यदि व्यापारी बड़ी मात्रा में उत्पाद बेचने में सक्षम होता है, जिससे बड़े व्यापारियों को फायदा होता है। छोटे व्यापारियों के लिए, यह नकदी से बदलाव करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान नहीं करता है।

नकद रहित लेन–देन में सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय :–

नकद रहित अर्थव्यवस्था के विचार को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान चैनलों पर वित्तीय सुरक्षा अनिवार्य है। जब हाल ही में, लाखों डेबिट कार्डों का डेटा हमलावरों द्वारा आसानी से चुरा लिया गया था, भारतीय

वित्तीय संस्थानों की इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा और एक्सचेंजों को सुरक्षित रखने की क्षमता सवालों के घेरे में आ गई थी। इसके अलावा, एक बड़ा कारण है कि लोग नकदी को पसंद करते हैं क्योंकि वित्तीय धोखाधड़ी आम व्यक्ति के लिए बहुत आम और जटिल हो गई है। एंटी फ्रॉड सिस्टम में बड़ी रकम का निवेश किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए जोखिम कम करने के उपकरण काफी मजबूत हो गए हैं और अब पारंपरिक भुगतान प्रणालियों से आगे निकल गए हैं।

भारत उन अर्थव्यवस्थाओं के मॉडल को ध्यान में रख सकता है जो पहले ही नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ चुके हैं। उरुग्वे ने व्यापारियों को डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहन दिया है। भारत को भी ऐसा करने के बारे में सोचने की जरूरत हो सकती है। स्वीडन एक और उदाहरण है। पूर्ण विस्तार के बाद भी, स्वीडन जैसी पूरी तरह से वित्तीय रूप से डिजिटाइज्ड अर्थव्यवस्था अभी भी अपने नकद लेनदेन का लगभग 20 प्रतिशत नकद में करती है।

क्रेडिट सिस्टम विभिन्न भुगतान विधियों का समर्थन करता है, कार्ड से – क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड और किसी भी जारीकर्ता से अंतरराष्ट्रीय डेबिट कार्ड – बैंक हस्तांतरण, प्रत्यक्ष डेबिट, फोन क्रेडिट, भुगतान खातों या इलेक्ट्रॉनिक धन जैसे विकल्पों के लिए। प्लेटफॉर्म की मोबाइल वॉलेट सुविधा उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदे जा रहे उत्पाद या सेवा के लिए सबसे उपयुक्त भुगतान विधियों को चुनने के लिए एक साथ लाती है। प्लेटफॉर्म साझा क्षैतिज घटकों की पेशकश करता है जो न केवल अतिरिक्त परिदृश्यों को पेश करके बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को उत्पन्न करता है बल्कि वफादारी और कूपनिंग जैसी अतिरिक्त मूल्य सेवाओं को भी सक्षम करता है। क्रेडिट वैकल्पिक भुगतान पद्धति के रूप में फोन क्रेडिट की पेशकश करके डिजिटल सामान और सेवाओं की बिक्री के लिए विशिष्ट सहायता प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं के साथ, मंच इतालवी मोबाइल–टेलीफोन ऑपरेटरों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा को रेखांकित करता है। जो चीज इसे अलग करती है वह है एनरिचमेंट फंक्शनलिटी, एक ऐसी तकनीक जो उपयोगकर्ता को उनके टेलीफोन नंबर के माध्यम से पहचानती है और तेज, सरल और सुरक्षित भुगतान अनुभव प्रदान करती है।

निष्कर्ष :–

भारत जैसे विशाल देश में, जहाँ की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को विवश है, नकद रहित अर्थव्यवस्था को लागू करने में कठिनाइयाँ स्वाभाविक हैं लेकिन इस दिशा में प्रयास शुरू करना आवश्यक है। आज डिजिटल मीडिया के माध्यम से डिजिटल लेन–देन के प्रति लोगों की मानसिकता में एक बड़ा बदलाव आया है।

लोगों को पता चल गया है कि डिजिटल लेन–देन सुरक्षित, आसान, सुविधाजनक और पारदर्शी भी है और भारत में नकदी में काले धन और नकली मुद्रा की कोई गुंजाइश नहीं है। नकद या नकद रहित इंडिया एक अभियान है जो हाल ही में शुरू किया गया है जिसे भारत सरकार डिजिटल मीडिया से नकद आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आगे बढ़ रही है और इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास कर रही है। उपरोक्त विश्लेषण से ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षित और निम्न शिक्षित लोग नकद रहित लेन–देन के बारे में जागरूक हैं।

जब हम नकद रहित लेन–देन के उपयोग पर विचार करते हैं, तो अधिकांश उच्च शिक्षित लोग अक्सर

नकद रहित लेनदेन का उपयोग कर रहे होते हैं। निरक्षर लोग इस अवधारणा को अपने दैनिक जीवन में तकनीकी प्रगति, जानकारी की कमी, रुचि की कमी, उनकी उम्र, सुविधा की कमी, बुरी धारणा आदि जैसे कई कारणों से नहीं अपना सकते हैं। यह अवधारणा तभी सफल होगी जब सभी अपने जीवन में अमल करने लगेंगे। तभी हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश कुछ हद तक विकसित है।

संदर्भ सूची :-

1. जाशिम खान और मार्गरेट क्रेग–लीस (2014), नकद रहित लेन–देन खरीद व्यवहार पर उनका प्रभाव ऑकलैंड विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थशास्त्र की समीक्षा, खंड 1, एन.1 आईएसएसएन 1647–1989
2. दीपिका कुमारी, नकद रहित लेन–देन मेथड्स, एप्लीकेशन्स एंड चेलेंजेस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनहैंस्ड रिसर्च इन एजुकेशनल डेवलपमेंट (IJERED) वॉल्यूम। 4 अंक 6, नवंबर–दिसंबर, 2016
3. डॉ. हितेश कपूर (2016), ग्राहक संतुष्टि और ई–बैंकिंग सेवाएं ट्राईसिटी का एक केस स्टडी, विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अभिनव अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल वॉल्यूम। 4, अंक 10, अक्टूबर 2015, आईएसएसएन 2319–8753
4. करमजीत कौर एट अल (2016) भारत में ई–कॉमर्स पर ई–पेमेंट सिस्टम जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च एंड एप्लीकेशन, ISSN: 2248–9622, वॉल्यूम 5, अंक 5, और (भाग 6) मई 2015, पीपी 63–73
5. सुश्री वी. कोकिला, (2017), काव इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट।
6. ओकोए, पी.वी.सी., और एजेजियो फॉर, आर. (2018) नाइजीरियाई अर्थव्यवस्था के विकास में नकद रहित अर्थव्यवस्था नीति का मूल्यांकन। रिसर्च जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, 4(7), 237–252
7. सैनी, बी.एम., डिमोनेटाइजेशन – मेटामोर्फोसिस फॉर नकद रहित इंडिया, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च (आईजेएसआर), वॉल्यूम 5, अंक 12, दिसंबर 2016ण